

राज कुमार मौर्य

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,

रामबाग, बिहटा, पटना

B.A. II Year (H.) Paper-III

विषय - संघ लोक सेवा आयोग

ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम, 1935 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया, स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान समय में इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा इन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। समय से पूर्व सदस्यों को असमता व कदाचार के आधार पर हटाया जा

(1)

सकता है, किन्तु इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जांच करवाई जाती है। जांच के पश्चात इस रिपोर्ट के आधार पर इसे हटाने या न हटाने का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिखा जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग की स्वतन्त्रता को बनाए रखने हेतु इसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते भारत की संघीय नीति पर धारित होते हैं।

आयोग के अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार की सेवा के अन्तर्गत कोई अन्य पद धारण करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। परन्तु आयोग के सदस्य इस आयोग के अन्तर्गत सचिव अथवा अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

⇒ अधिल भारतीय सेवाओं के लिए यह आयोग विभिन्न प्रातियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने का कार्य करता है।

⇒ जब दो या इससे अधिक राज्य अपने यहां एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव करें तो आयोग के द्वारा यह कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

⇒ भारत सरकार के द्वारा लोक सेवकों की प्रोन्नति, प्रातियुक्ति तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के ~~संबंध~~ विषय में आयोग के द्वारा परामर्श किया जाता है।

⇒ भारत सरकार के कर्मिक मन्त्रालय द्वारा अधिल भारतीय सेवाओं के प्रारूप में परिवर्तन की अनुशंसा मांगे जाने पर आयोग उन्हें अनुशंसा उपलब्ध-

करवाता है।

⇒ संघ लोक सेवा आयोग को सभी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, यह भारत के किसी भी नागरिक को सम्मन भेज सकता है तथा ~~यह~~ आयोग के द्वारा किसी भी विभाग की रिपोर्ट की मांग की जा सकती है।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रति वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे राष्ट्रपति संसद के सम्मुख प्रस्तुत कराते हैं।